थावरचंद गहलोत ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण से सम्बन्धित विषयों पर आधारित पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में असम,अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकरिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री एन.एस. कंग तथा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के केन्द्रीय अधिकारी व सम्बन्धित राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे।

अपने उद्घाटन भाषण में, श्री थावरचंद गहलोत कहा कि नया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांग जनों के अधिकारों को व्यापकता प्रदान किया है और साथ ही साथ पुराने दिव्यांग जन अधिनियम, 1995 को निरस्त किया है। नया अधिनियम राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह जिम्मेदारी देता है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि दिव्यांग सामान्य नागरिकों के समान ही अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे दिव्यांग क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं के पंजीकरण हेतु संस्थागत अवसंरचना विकसित करें। यहां यह जानकारी देना आवश्यक नही है कि नये अधिनियम में इसके प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है।

उन्होंने कहा कि विभाग दिव्यांग के विशिष्ट पहचान पत्र की एक योजना को कार्यान्वित करने जा रहा है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों का एक डाटाबेस तैयार किया जा सके और प्रत्येक दिव्यांग को विशिष्ट पहचान पत्र निर्गत किया जा सके।

श्री गहलोत ने आगे कहा कि उनका मंत्रालय 5300 से अधिक एडीआईपी कैम्प आयोजित कर चुका है। एडीआईपी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों द्वारा टिकाऊ, आधुनिक, स्तरीय तथा वैज्ञानिक तरीके से निर्मित यंत्रों और उपकरणों को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। इन यंत्रों और उपकरणों से दिव्यांगों की शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुर्नवास में मदद मिलेगी।

अपने सम्बोधन में श्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत सरकार ने दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कई उपयोगी योजनाएं प्रारंभ की हैं। उन्होनें आशा जताई कि इस सम्मेलन में व्यक्त किये गए विचारों से सभी संबंधित विभागों/लोगों को लाभ होगा। दिव्यांग जन हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई सभी योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस क्रम में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चार क्षेत्रीय सम्मेलन पहले ही आयोजित किये जा चुके है- 11 मई, 2017 को मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन ; 12 मई, 2017 को चेन्नई में दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन; 26 मई, 2017 को चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन तथा 2 जून, 2017 को भोपाल में मध्य क्षेत्रीय सम्मेलन।

सम्मेलन के दौरान पूर्वी राज्यों से संबंधित निम्नलिखित एजेंडे पर चर्चा हुई

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 पर चर्चा और इसके कार्यान्वयन में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की भूमिका।

विभाग की निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा

सुगम्य भारत अभियान की प्रगति

एसआईपीडीए योजना के तहत उपयोग प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति।

डीडीआरसी योजना।

अन्य विषय जैसे सीआरसी/डीडीआरएस/एडीआईपी/ कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना/छात्रवृति योजनाएं/डीबीटी की कार्य प्रगति।

यूडीआईडी योजना के तहत दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करना।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया जो 19 अप्रैल,2017 से लागू हो गया है। नये अधिनियम में दिव्यांगों को बहुत सारे अधिकार दिये गये है। नया अधिनियम राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों पर यह जिम्मेदारी देता है कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि दिव्यांग दूसरे नागरिकों के समान ही अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। यह अधिनियम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को यह जिम्मेदारी देता है कि वे ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम बनाए तथा ऐसी अवसंरचना विकसित करें कि दिव्यांगों का सशक्तिकरण और समावेश सुनिश्चित हो सके। केन्द्र सरकार अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को नए तरीके से निर्मित करने की प्रक्रिया में संलग्न है और राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों से यह आशा की जाती है कि वे भी अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में तदनुसार परिवर्तन करें। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने आज आईआईएम शिलांग का दौरा किया

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डा0 महेन्द्र नाथ पांडेय ने आज भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग का दौरा किया। मंत्री जी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के मौजूदा कॉम्पलेक्स एवं सभागार, जिसमें डा0 कलाम ने अपना अंतिम भाषण दिया था, सहित सभी परिसरों के अवलोकन के लिए ले जाया गया। इस दौरान डा0 पांडेय का संस्थान में स्वागत किया गया जिसके बाद उन्होंने निदेशक तथा संकाय सदस्यों के साथ क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। संस्थान की प्रगति से प्रसन्न डा0 पांडेय ने वहां उपस्थित लोगों को आने वाले दिनों में निरंतर प्रयास जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के मानक बरकरार रखने में समर्थ हो सकें। उन्होंने उल्लेख किया कि संस्थान का प्रत्येक सदस्य दिल से काम कर रहा है। यही स्वामित्व की भावना भविष्य में संस्थागत निर्माण का कारण बनेगी।

माननीय मंत्री ने महसूस किया कि भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग को निरंतर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों पर फोकस करने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना चाहिए जिससे कि यह पूरे भारत के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के समस्त विकास के लिए भी सहायक हो सके। उन्होंने संस्थान के नेतृत्व को प्रधानमंत्री मोदी के सर्वांगीण सामाजिक विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर बधाई दी।

विचार-विमर्श के दौरान संस्थान के निदेशक ने 10 वर्ष की अवधि के दौरान संस्थान के विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों की निरंतर उपलब्धियों की कहानियां सुनाई। उन्होंने मंत्री जी को एपीजे अब्दुल कलाम नीति अनुसंधान तथा विश्लेषण केन्द्र की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा पूर्वोत्तर परिषद की सहायता के बारे में बताया। प्रो0 डे ने बताया कि इस केन्द्र का उद्देश्य 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों- पर्यटन, बीपीओ, लॉजिस्टिक, हथकरघा तथा हस्तशिल्प में विकासात्मक संरचना तैयार करना है।

आपके अन्दर के तस्वीरकार को जगाओ और बेरफुट फोटोग्राफी कन्टेस्ट में हिस्सा लें

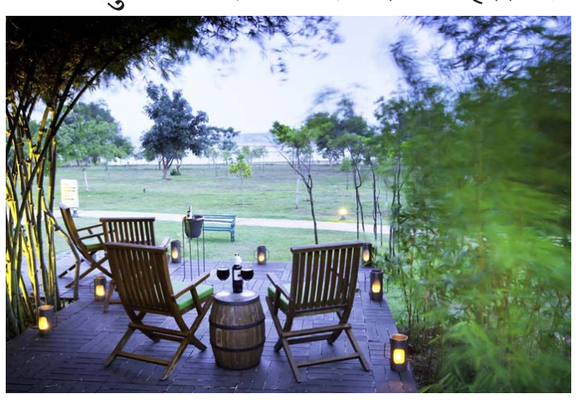

अहमदाबाद: एक उत्कृष्ट तस्वीर क्लिक करने का काम पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन इसकी तैयारी में जीवन निकल जाता है। फोटोग्राफी एक परिश्रम मांगनेवाला जोशीला काम है, लेकिन यह प्रेरणात्मक परिणाम भी प्रदान करता हैं। दी सेराई एन्ड बेरफुट रिसोर्ट ने अपनी बेजोड़ शटरबग फोटोग्राफी कन्टेस्ट की द्वितीय आवृति शुरू की हैं। जिसमें विन्युल स्टोरीटेलर्स को दी सेराई एन्ड बेरफुट रिसोर्ट्स में अपने स्टे की अदभूत सुन्दर पलो एवं अनुभव मढ लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। दी शटरबाग फोटोग्राफी कन्टेस्ट की संकल्पना महेमान को दी सेराई एन्ड बेरफुट रिर्सोट्स आपके मुकाम के दौरान विविध लेन्डस्केप्स को मढ़ने के लिए मंच देनेवाला है। फोटोग्राफी कन्टेस्ट को गत वर्ष अपवादात्मक सहभाग सहित उत्तम प्रतिसाद मिला था और अब फोटोग्राफी शौकिनो को आकर्षित करती सेराई रिसोर्ट्स की स्थापित वार्षिक प्रोपर्टी बनी हैं।

लेन्डस्केप एवं स्टार ट्रेइल से टाईम लेप्स एवं नाइट फोटोग्राफी तक दी सेराई रिसोर्ट्स में महेमान अपनी फोटोग्राफी प्रतिभा की खोज कर सकते हैं और सेंकड़ों सुन्दर स्थलो पर पहुंच सकते हैं। यह स्पर्धा काबिनी, बंडीपुर, चिकमंगलुर में दी सेराई रिसोर्ट्स तथा अदमान के बेरकूट रिसोर्ट्स में रहनेवाले सभी महेमानों के लिए खुली हैं। ट्रावेल फोटोग्राफी अति लोकप्रिय विषय में से एक हैं और कैमरा पर क्लिक करने हेतु काफी कुछ अदभूत स्थल तैयार हैं। ये स्थल उनके लोगों, संस्कृति, लेन्डस्केप एवं निसर्ग सहित देखने का मौका प्रदान करता हैं। (22-1)

नीति आयोग ने ''साथ'' कार्यक्रम का शुभारंभ किया

नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए ''साथ'' यानी 'सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल' अर्थात् मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प करना है। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता पूरी करेगा।

''साथ'' का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए राज्यों के तीन भावी 'रोल मॉडलों' का चयन करना और उनका निर्माण करना है। नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों की मशीनरी के साथ सहयोग करते हुए हस्तक्षेप का सुदृढ़ रोडमैप तैयार करेगा, कार्यक्रम कार्यान्वयन का ढांचा विकसित करेगा और निगरानी एवं अन्वेषण व्यवस्था कायम करेगा। इसके अंतर्गत संस्थागत उपायों के जरिए राज्यों की विभिन्न प्रकार की सहायता की जाएगी।

नीति आयोग ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया था, जिनमें से 14 राज्यों ने अपने प्रेजेंटेशन किए, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोआ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों ने अपने परियोजना प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य श्री विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।

इन 14 राज्यों में से पांच का चयन किया गया है। इनमें से 3 राज्यों का चयन अंतिम रूप से किया जाना है, जिनमें यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

नीति आयोग ने ''साथ'' कार्यक्रम का शुभारंभ किया

नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए ''साथ'' यानी 'सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल' अर्थात् मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प करना है। यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता पूरी करेगा।

''साथ'' का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए राज्यों के तीन भावी 'रोल मॉडलों' का चयन करना और उनका निर्माण करना है। नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों की मशीनरी के साथ सहयोग करते हुए हस्तक्षेप का सुदृढ़ रोडमैप तैयार करेगा, कार्यक्रम कार्यान्वयन का ढांचा विकसित करेगा और निगरानी एवं अन्वेषण व्यवस्था कायम करेगा। इसके अंतर्गत संस्थागत उपायों के जरिए राज्यों की विभिन्न प्रकार की सहायता की जाएगी।

नीति आयोग ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया था, जिनमें से 14 राज्यों ने अपने प्रेजेंटेशन किए, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोआ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों ने अपने परियोजना प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य श्री विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।

इन 14 राज्यों में से पांच का चयन किया गया है। इनमें से 3 राज्यों का चयन अंतिम रूप से किया जाना है, जिनमें यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

Sony LePlex FPC 12 June, 2017

India Time	12-Jun-17 Monday
6:00 AM	STEVE JOBS
8:52 AM	RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT! S03E12
9:53 AM	MONSTERS UNIVERSITY
12:07 PM	VAN HELSING
2:26 PM	RAMBO: FIRST BLOOD 2
4:30 PM	FINDING NEMO
6:49 PM	DEATH RACE 3
9:00 PM	SPIDER-MAN 3
12:01 AM	ANACONDA 2
1:58 AM	GOOSEBUMPS
3:38 AM	BARB WIRE

डिजिटल इंडिया: २५००० वाईफाई लगाएगा बीएसएनएल

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में २५००० वाईफाई स्पोट लगाने का फैसला किया हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार का संचार मंत्रालय बीएसएनएल के साथ एक समझौता पत्र पर दस्तखत करेगा। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। खबर के मुताबिक बीएसएनएल वाईफाई होटस्पोट लगाने का ठेका आईटीआई को देगा। दरअसल बीएसएनएल सिर्फ इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाता है जबकि वाईफाई इक्विपमेंट बनाने का काम आईटीआई के जिम्मे होता हैं। बताया जा रहा है कि सरकार भविष्य में इसका विस्तार करेगी। गौरतलब है कि केन्द्र की मोदी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह के प्रयास कर रही हैं। शासन में पारदर्शिता एवं गति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवाओं को ओनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा हैं।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्प्लेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E : alpaviram1@yahoo.com

'सागरमाला' देश के विकास में गेम चेंजर है: पहली कार्यशाला राजधानी में आयोजित

शिपिंग मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में अपने प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला पर अमल में तेजी लाना राज्यों के साथ साझेदारी पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सागरमाला कार्यक्रम के लिए शिपिंग मंत्रालय, अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों और भारत के विभिन्न समुद्र तटवर्ती राज्यों के बीच साझेदारी बढ़ाना था।

इस कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव (शिपिंग) श्री राजीव कुमार ने की और इस अवसर पर मुख्य भाषण नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने दिया। इस अवसर पर श्री अमिताभ कांत ने कहा कि बंदरगाह आर्थिक विकास के उत्प्रेरक साबित हो सकते हैं और इसके साथ ही वे देश में निरन्तर 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अत: ऐसी स्थिति में सागरमाला कार्यक्रम देश के विकास में गेम चेंजर साबित होगा।

चीन, कोरिया, जापान, और सिंगापुर की सफलता की गाथाओं का उल्लेख करते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि समुचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए समस्त हितधारकों का समूह बनाने की जरूरत है और इसके साथ ही निर्यात पर केन्द्रित रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि चीन, कोरिया, जापान, और सिंगापुर में बंदरगाहों की अगुवाई में देश का तेजी से विकास हुआ है। भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 7.6 फीसदी के स्तर पर ले जाने के लिए वैश्विक बाजारों में पैठ बनाना आवश्यक है जिसमें केवल बंदरगाह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि भूमि कोई चुनौती नही है और मुख्य जरूरत इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय वस्तुओं को वैश्विक बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं के समकक्ष बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना अत्यन्त जरूरी है और यह तभी संभव हो पाएगा जब बंदरगाह आगे चलकर विनिर्माण केन्द्रों (हब) में तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने भारत में क्रूज पर्यटन की असीम संभावना होने की बात दोहराई और सभी तटीय राज्यों से अपील की कि वे इसे बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कार्य करें।

सचिव (शिपिंग) श्री राजीव कुमार ने उद्घाटन सत्र में कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के प्राधिकरणों की ओर से सक्रिय भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सागरमाला कार्यक्रम नियोजन के चरण से आगे बढ़कर अब क्रियान्वयन के चरण में पहुंच गया है और तीन ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ी परियोजनाओं का काम राज्यों को अपने हाथ में लेना चाहिए। कनेक्टिविटी का विस्तार करना, क्रूज शिप का विकास करना और तटीय नौवहन को बढ़ावा देना इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल हैं। उपर्युक्त कार्यशाला का उद्देश्य मुख्य हितधारकों को सागरमाला कार्यक्रम के प्रावधानों, इसके उद्देश्यों और सागरमाला के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उनके लिए उपलब्ध अवसरों से परिचित कराना था।

कार्यशाला में समुद्र तटवर्ती राज्यों के प्रधान सचिवों, बंदरगाहों के प्रमुखों और सम्बन्धित मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

सागरमाला कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हितधारकों के साथ बेहतर संवाद सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तत्वावधान में अगले 6-8 महीनों के दौरान अनेक कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई है।

तमिलनाडु में कामराजार बंदरगाह नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया

केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सागरमाला के तहत तमिलनाडु में 2.5 लाख करोड़ रूपये का निवेश किया। इसमें से 39,000 करोड़ रूपये बंदरगाह के आधुनिकीकरण, 55,000 करोड़ रूपये बंदरगाह संपर्क एवं 1,50,000 करोड़ रूपये बंदरगाह केन्द्रित औद्योगिकीकरण के लिये होंगे। मंत्री महोदय ने आज चेन्नई में कामराजार बंदरगाह में यह बात कही जहां उन्होंने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया ।

इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रूपये के बराबर का एक नया कंटेनर टर्मिनल, 151 करोड़ रूपये बराबर का एक नया मल्टी कार्गो टर्मिनल, 60 करोड़ रूपये के बराबर का कंटेनर तक रेल पटरी एवं मल्टी कार्गो टर्मिनल, 11.82 करोड़ रूपये के मूल्य की आरएफआईडी प्रणाली शामिल हैं।

नया कंटेनर टर्मिनल परियोजना का विकास व्यापारियों के लिए अधिक कंटेनर हैंडलिंग सुविधा उपलब्ध करायेगा। यह बंदरगाह के आस-पास क्षेत्र में नये उद्योगों एवं सहायक उद्योगों में भी सहायता करेगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करायेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

नई कार्गो टर्मिनल परियोजना का विकास व्यापारियों के लिए अधिक मल्टी कार्गो हैंडलिंग सुविधा प्रदान करेगा । यह बंदरगाह के आस-पास क्षेत्र में नये उद्योगों एवं सहायक उद्योगों में भी सहायता करेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करायेगा। कंटेनर तक रेल पटरी एवं मल्टी कार्गो टर्मिनल परियोजना रेल मार्ग के जरिये कार्गो की आवाजाही के बेहतर बनायेगी। यह टर्मिनल लॉजिस्टिक लागत मे कमी लाएगी तथा सड़कों पर बोझ घटाएगी। इससे आस-पास के क्षेत्र में सड़कों पर जाम लगने की स्थिति में कमी आयेगी जिससे आम लोगों को लाभ पहुँचेगा। आरएफआईडी प्रणाली के क्रियान्वयन की परियोजना व्यापारियों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ाएगी। आरएफआईडी प्रणाली से कार्गो ट्रैफिक के भीड़-भाड में कमी आयेगी जिससे समय की बचत होगी और बंदरगाह के संचालनों में बढ़ोतरी होगी।

फादर्स डे मनाये अमूल्य प्लेटिनम के साथ

फादर्स डे आपके जीवन का विशेष व्यक्ति कि जो आपके दिल के नजदीक हैं उनके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त कर मनायी जाती है। आपके जो संबंध आपके पिता के साथ हैं , वैसा और कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता और विशेष व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों को अमूल्य प्लेटिनम से गिफ्ट देने से अच्छा क्या हो सकता हैं। प्लेटिनम की अन्दुरूनी मजबूताई और अनगिनत गुणवत्ता आपके पिता जैसी हैं जो आपके जन्म से ही आपके साथ मजबूताई से खड़े हैं ।

प्लेटिनम कलैक्सन मॉर्डन पुरूष को ध्यान में रखकर डिजाइन की गयी है। यह डिजाइन भूमितीक डिजाइन से प्रेरित हैं । क्लासिक चेन से रीन्ग और ब्रेसलेट तक हरेक पीस इस तरह डिजाइन है जो एक भावनाशील और मजबूत व्यक्ति के लिए शोभायमान हैं।

प्लेटिनम मजबूताई और आत्म विश्वास का प्रतिक हैं और प्रेम का तथा अहोभाव की पेशकश के लिए एकदम योग्य भेंट है। -

एनपीए वसूली के लिए पीएनबी ने अपनाया गांधीगिरी का नया रास्ता

एनपीए वसूली के लिए पंजाब नैशनल बैंक ने नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत से ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए बैंक ने इस बार एक नया तरीका गांधीगिरी अपनाया है। इसके तहत पंजाब नैशनल बैंक के मण्डल कार्यालय अहमदाबाद द्वारा वरिष्ठ अधिकारीयों की अगुवाई में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया जो कि ऐसे कर्जदारों के, जो बैंक का पैसा लेकर भूल गए हैं तथा समाज में बड़े ही शान शौकत से अपना जीवनयापन कर रहे है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उसी समाज में नीचा दिखाकर भावनात्मक रूप से बैंक का कर्ज लौटाने का बड़े ही विनम्र तरीके से आग्रह किया जा रहा है, इस अभियान में बैंक की टीम जिस मौहल्ले में भी हाथों में बैनर, तख्ती लिए पहुँचती है तो लोगों का हुजूम लग जाता है तथा कर्जदाता जो कि उसी समाज में इतने दिन बड़े शान शौकत से जी रहा था कहीं न कहीं लज्जित महसूस करता है। पीएनबी को इस अभियान में सफलता भी मिल रही है, पिछले कुछ दिनों में बैंक की रिकवरी राशि में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस अभियान में बैंक के सभी स्टाफ सदस्य पूरे जोश के साथ भाग ले रहें तथा अभियान की सफलता से सभी के हौसले बुलंद हैं।

'डिजीयात्रा' विमान यात्रियों के लिए एक नया डिजिटल अनुभव

नागरिक उड्डयन मंत्रालय डिजीयात्रा प्लेटफॉर्म के जरिये विमान यात्रियों को डिजिटल अनुभव कराने जा रहा है। 'डिजीयात्रा' उद्योग जगत की अगुवाई में एक विशिष्ट पहल है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप अपनी ओर से सहयोग प्रदान करेगा, जिसके तहत देश को डिजिटल ढंग से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है। यह कदम एयर सेवा के बाद उठाया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता शिकायतों के निवारण एवं वास्तविक समय पर डेटा प्रसारित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर एकजुट किया जाएगा।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू ने उम्मीद जताई कि डिजीयात्रा पहल से विमान यात्रियों के हवाई सफर अनुभव में व्यापक बदलाव आएगा और इसके साथ ही भारतीय उड्डयन क्षेत्र की गिनती दुनिया के सर्वाधिक अभिनव हवाई नेटवर्कों में होने लगेगी।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने आज 'डिजीयात्रा' पर रिपोर्ट पेश की। श्री सिन्हा ने इस अवसर पर मंत्रालय की 'डिजीयात्रा' पहल के बारे में मीडिया को जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि 'डिजीयात्रा' पहल का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल परितंत्र विकसित करने के लिए समूचे उद्योग जगत को एकजुट करना है, जिससे विमान यात्रियों को अपने सफर के दौरान एक निर्बाध, निरंतर एवं कागज रहित सेवा का अदभुत अनुभव होगा।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री सिन्हा ने यह जानकारी दी कि मंत्रालय ने एक तकनीकी समिति का गठन किया है, जिसमें उद्योग जगत के हितधारक शामिल हैं। यह समिति 30 दिन के अंदर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। इन सिफारिशों पर आम जनता की टिप्पणियां भी प्राप्त की जाएंगी और इन पर अगले 30 दिनों तक परिचर्चाएं होंगी। इसके बाद एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

श्री सिन्हा ने कहा कि डिजीयात्रा पहल का उद्देश्य भारत में हवाई सफर करने वालों को अपनी यात्रा के दौरान अभिनव एवं डिजिटल ढंग से एकीकृत उड़ान अनुभव प्रदान करना है।

सूचना

कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई-मेल पर ही भेंजे :

alpaviram@gmail.com